खबर संक्षेप

बांस शिल्पकला पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम 15 अक्टूबर से

मण्डला। भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बांस शिल्पकला पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम आमानाला मण्डला में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले समाज के विभिन्न वर्गों के युवाओं (पुरूष/महिला) को रोजगार को अपनाने के लिये प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नये उद्यम को बढ़ावा देना, मौजूदा एसएमएसई क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में न्यूनतम 25 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया जाना है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी उत्तीर्ण, मण्डला जिले का निवासी हो, आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना केवाईसी दस्तावेज कार्यालय में जमा करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पौष्टिक खाद्य पदार्थो एवं स्वदेशी खिलौने की जागरूकता शिविर

मण्डला। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में आठवे राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का आयोजन जन आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आज पोषण माह की थीम अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्थानीय उत्पादों/खिलौनों/पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग एवं स्वयं निर्मित स्वदेशी खिलौने/स्थानीय व्यंजनों का प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

पैसा देने के बावजूद आज दिनांक नहीं लगाया ट्रांसफार्मर

विद्युत ठेकेदार की मनमानी

*** मेरे मामा 'डी' है तुम किसान मेरा क्या कर लोगे।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

एक ओर जहां केन्द्र एवं राज्य की सरकार किसानों के हितार्थ विभिन्न तरह की योजनायें क्रियान्वित कर रहे हैं किसानों को बिजली, पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो इसके लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन एक ओर तो विद्युत विभाग की लापरवाही और दूसरा विद्युत विभाग के अधिकारियों के रिश्तेदारों की ठेकेदारी ने किसानों के हक पर डांका डाल रखा है आखिर पैसा जमा करने के बावजूद पिछले 10 माह से परेशान किसानों की मदद कौन करेगा।

मामला है नैनपुर विकासखण्ड के ग्राम निवारी का जहां के किसानों ने जेई नैनपुर से बात करने के बाद ठेकेदार बॉबी खान को 02 लाख रूपये एडवांस दिसम्बर 2024 में दिये लेकिन आज दिनांक तक न तो ट्रांसफार्मर लगा और न ही किसानों को बिजली की सुविधा प्राप्त हुई। बार-बार विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा लेकर जाते किसानों को कोई मदद नहीं मिली और ठेकेदार महोदय हैं कि किसानों को ही इस बात को लेकर चमकाते हैं कि मेरे मामा 'डी' साहब है लिहाजा तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। अलग से 50 हजार दोगे तो ट्रांसफार्मर लगेगा नहीं तो जहां लगे शिकायत करो।

पिछले 10 माह से परेशान किसानों ने कल जनसुनवाई पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी जिसमें उल्लेख किया गया कि हम सभी किसान दिनांक 29/11/2024 को म.प्र. विद्युत मंडल निवारी गये थे, वहाँ पर जे ई नैनपुर आफिस से बात होने पर आपरेटर ब्रजेश नाथ को संपर्क करने को कहा गया, आपरेटर ने बोबी खान (श्यानवसी अहमद) नैनपुर ठेकेदार को फोन लगाया गया जिससे आमने सामने बात होने पर सिंचाई हेतु 63 केव्हीए का विद्युत ट्रांसफारमर लगाये जाने की बात हुई थी।

जिसकी कुल राशि 225000.00 (दो लाख पच्चीस हजार) जिसमे 11/12/2024 तक कुल 2 लाख रुपये फोनपे पर अलग-अलग दिनॉक पर ट्रांसफार किये गये थें।

पिछले 8 महिने में सिर्फ फोन पर बातचीत होने पर कल लगा दूँगा, कल लगा दूँगा करके 8 माह बीत गये है।

किसानों की आर्थिक स्थिति वैसी भी खराब चल रही है। और विद्युत ठेकेदार द्वारा समय पर काम नही किया जा रहा है। विद्युत ठेकेदार बोबी नैनपुर का मोबाईल नं. 9098603865 है। इस ठेकेदार के द्वारा हमारे ही नही बल्कि अन्य किसानों को साल मे और दो साल परेशान करके अपनी मनमानी करते हुये लाखों रुपये डकारने की कोशिश करते चले आ रहे है।

विद्युत विभाग नैनपुर मे लिखित शिकायत करने पर दिनोंक 14/06/2025 को कनिष्ठ यंत्री महोदय के सामने विद्युत ठेकेदार के द्वारा लिखित रुप मे आश्वासन दिया गया कि 17/06/2025 तक विद्युत ट्रांसफारमर लगाकर लाईन सुचारु रुप से चालू कर दी जावेगी। पर आज दिनॉक तक विद्युत ट्रांसफारमर नही लगा है। सहमति पत्र की छायाप्रति आपकी ओर अग्रेषित है।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि०क.लि. जबलपुर लिखित आवेदन को स्पीड पोस्ट करने पर दिनाँक 22/08/2025 को जाँचकर्ता अधिकारी के रुप मे कार्य. अभि. (एसटीसी-एसटीएम) म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.क.लि मण्डला को भेजा गया जिसमे जॉच रिपोर्ट आना बाकी है।

इस कार्य पर यह पाया गया कि ट्रांसफारमर डीपी की पूरी फिटिंग नहीं की गई है। ट्रांसफारमर डीपी का एक पोल भी टूटा हुआ है तार झूल रहे है। अर्थिंग नही गई है। डी पी एंव एल टी पोल मे स्टे भी नह नही लगाये गयें है। एल टी लाईन के तार भी टुकड़े टुकड़े में लगाये गये है।

विद्युत ट्रांसफारमर 63 केव्हीए लगाये जाने की बात हुई थी पर मौकाये जॉच पक्ष देखा गया की 25 केव्हीए के ट्रांसफारमर पर 63 केव्हीए की स्लीप लगाकर किसानो से धोखाधड़ी की जा रही है।

ट्रांसफारमर को लोहे के एंगल के ऊपर तार से बाँधकर रखा गया है। और न ही डी पी पर स्टे लाईन लगी है। इसी लाईन के बाजू में एक और विद्युत ट्रांसफारमर 63 केव्हीए का लगा है जिस पर एक बार पोल गिर चुका है। जिससे जान माल दुर्घटना का अशंका बनी हुई है।

एल टी लाईन के अंतिम छोर पर न ही डिस्ट्रीब्युशन बाक्स लगा है जिससे किसानो को हुक लगाकर कार्य करने पर मजबूर है।

कार्य पूरा नही होने पर दिनॉक 13/06/2025 को शिकायत की गई इसके बावजूद शेष कार्य को पूरा करने के लिये बॉबी द्वारा अतिरिक्त 50 हजार की मॉग की जा रही है जबकि सभी किसानों के द्वारा बॉबी के साथ कुल दो लाख पच्चीस हजार में पूरा काम करने की लिखित सहमति दी गई थी।

इस कार्य को विद्युत विभाग नैनपुर द्वारा बॉबी ठेकेदार के द्वारा करने को कहा गया इसके अलावा अन्य किसी ठेकेदार को इस कार्य के लिये सहमति घोषणा पत्र पर किसी भी किसान के द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये है।

म.प्र.पू.क्षे.वि.वि०क.लि. निवारी नैनपुर में ट्रांसफारमर लगाने का आवेदन देने से पहले पता नही था कि ठेकेदार और मण्डला डी के पारिवारिक संबंध है। बार बार लगाने को कहा गया पर ठेकेदार द्वारा कहा गया कि जाओ क्या कर लोगे, मेरा मामा डी है। मेरे ऊपर सभी बड़े अधिकारी का हाथ है। नही भी लागाऊँगा तो मेरा कुछ नही कर सकते।

जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक सम्पन्न

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में गोलमेज कक्ष में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछले बैठक के प्रतिवेदन के साथ नवीन औद्योगिक प्रक्षेत्रों मोहनिया पटपरा और हाथीतारा-गुंदलई के संबंध में जानकारी दी गई।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र से लगे औद्योगिक प्रक्षेत्रों के औद्योगिक भूखंडों में संचालित इकाईयों का पुनः सर्वे कराएं। औद्योगिक इकाई परिसरों में यदि श्रमिक आवास बनाये गये हैं तो राजस्व अधिकारी की अगुवाई में टीम गठित कर उनका वेरिफिकेशन कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में कोदो-कुटकी का उत्पादन होने एवं उपार्जन को देखते हुए मोहनिया पटपरा में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करें।

बैठक में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने देवदरा औद्योगिक प्रक्षेत्र में पावर कट की समस्या से अवगत कराते हुए, फीडर सेपरेशन का प्रस्ताव रखा। समीक्षा बैठक में जीएम डीआईसी श्री नंदकिशोर वास्कले, एलडीएम श्री सुजाय कुमार सहित संबंधित उपस्थित रहे।

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक संपन्न

मण्डला। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बाल भिक्षावृत्ति समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि विशेष अभियान संचालित करते हुए ग्रामों का सर्वे कराएं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी छात्रावास में 9 से 12वीं तक के बालिकाओं को अपराजिता अभियान के तहत प्रशिक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पॉक्सो पीड़ितों के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बाल देखरेख संस्था, बाल कल्याण समिति में प्रचलित प्रकरण, वनरेवल मैपिंग, घर पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टाफ सेंटर, बालिका लिंक अनुपात में सुधार हेतु अन्य गतिविधियां के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास शालिनी तिवारी, सहायक संचालक श्री रोहित बड़कुल, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गुप्ता सहित जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

सीईओ जिला पंचायत ने की ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शाश्वत सिंह मीना ने जिला पंचायत सभा कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने मनरेगा की समीक्षा करते हुए कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ अंतर्गत शत प्रतिशत कार्यों की स्वीकृति की जाये। एक बगिया मां के नाम की लक्ष्यपूर्ति 3 दिवस में करें। लेबर बजट अंतर्गत घुघरी जनपद की प्रगति 60 प्रतिशत से कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अक्टूबर माह में 60 प्रतिशत प्रगति लाई जाये। सभी सहायक यंत्री 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके कार्यों की सीसी जारी करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मीना द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पीएम जनमन आवास एवं प्रधानमंत्री आवास में शेष स्वीकृती एवं प्रथम किश्त पेंडिग हितग्राहियों को 15 दिवस में शत-प्रतिशत प्रथम किश्त जारी करने एवं तृतीय किश्त जारी सभी आवासों 30 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन में जनपद पंचायत बिछिया मोहगांव एवं मवई प्रथम किश्त पेंडिग हितग्राहियों का जनपद स्तर में बैठक आयोजित कर सीईओ जनपद के साथ जिला आवास प्रभारी बैठक कर निराकरण करायें।

समीक्षा बैठक में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण और उनके भुगतान किये जाने, प्रगतिरत कार्य, शेष कार्य की जानकारी ली गई। सीईओ श्री मीना ने कहा कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर केवल नर्मदा पथ, हाट बाजार, बस स्टेंड आदि में ही निर्मित किये जायेंगे। वाश आन व्हील अन्तर्गत कार्य करने वाले सफाई मित्रों को समस्त जनपदों से जोड़ने व उनके रोजगार बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में कार्यपालन यंत्री आरईएस, जिला पंचायत के सभी योजनाओं के जिला परियोजना अधिकारी, सभी जनपद पंचायत के सीईओ, सहायक यंत्री सहित संबंधित उपस्थित रहे।

ग्राम दानीटोला में अवैध मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक सील

*** अमानक व एक्सपायरी दवाइयाँ जब्त।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में संचालित दवा दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को ग्राम दानीटोला में संचालित मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में अमानक एवं एक्सपायरी दवाइयाँ पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही जप्त किया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि मेडिकल स्टोर किसी अन्य फार्मासिस्ट के नाम पर संचालित किया जा रहा था, जबकि संचालक के पास फार्मासिस्ट की मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं थी। गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक दोनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लापरवाही या अवैध संचालन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समाधान ऑनलाईन की समीक्षा 23 अक्टूबर को

मण्डला। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा 23 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे सीएम हेल्पलाईन के विभागों व विषयों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान की समीक्षा की जायेगी। अपर कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित जानकारी 17 अक्टूबर तक लोकसेवा गारंटी कार्यालय कलेक्ट्रेट में जमा करें तथा समीक्षा में समस्त जानकारी सहित उपस्थित होवें।

विडम्बना | **रिश्वतखोर डीपीसी को कौन दे रहा संरक्षण, रंगे हाथ पकड़ाने के बावजूद कुर्सी पर काबिज।**

सुशासन का कैसा उदाहरण दे रहा प्रशासन

*** शिक्षा विभाग बना लूट खसोट का अड्डा।**

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला

जिला शिक्षा केन्द्र जहां शिक्षा के विकास के अलावा हर वह कार्य हो रहे हैं जिससे अधिकारियों की बल्ले-बल्ले है। ऐसा कोई कार्य नही जिसके पीछे पैसा न हो, यहां के अधिकारी खुलेआम न केवल शिक्षकों से बल्कि कार्यकारी एजेंसियों से, छात्रावास अधीक्षकों से, ठेकेदारों से, निजी स्कूल संचालकों से और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन से लाखों का मोटा माल अंदर कर रहे हैं यह सब जगजाहिर है लेकिन जिला प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं यही कारण है कि ये अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेने की जुर्रत भी कर रहे हैं वह तो लोकायुक्त की कार्यवाही ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रंगेहाथों पकड़ा लेकिन वाह रे यहां के शासन-प्रशासन के प्रतिनिधि कि खुलेआम जिसके हाथ रिश्वत से रंगे हों वह जिले के भविष्य को संवारने के लिये आज भी जिम्मेदार पद पर काबिज है।

रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाये डी.पी.सी.

जिला आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। ट्रैप में पकड़े जाने के बाद भी संबंधित अधिकारी का पद पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि सरकार और प्रशासन भ्रष्ट अधिकारियों को खुली छूट दे रहे हैं।

विगत दिनों जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को 60,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगेहाथ पकड़ा था। आश्चर्य की बात यह है कि ट्रैप के कई दिन बीत जाने के बाद भी उक्त अधिकारी अपने पद पर कायम है और कार्यालय में बैठकर नियमित कार्य कर रहा है।

आम तौर पर ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित कर जांच पूरी होने तक पद से दूर किया जाता है ताकि जांच निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। लेकिन मंडला में प्रशासन ने न तो निलंबन की कार्रवाई की और न ही तबादले की आवश्यकता समझी।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि "यह सुशासन के खोखले दावों की पोल खोलता है। जब ट्रैप में पकड़े गए अधिकारी को भी संरक्षण मिले, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे?

जनता अब यह सवाल उठा रही है कि आखिर मंडला में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई केवल दिखावे तक ही सीमित क्यों है।

इस संबंध में जिला पंचायत के अध्यक्ष से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं मामले की पूरी जानकारी लेकर आपको अवगत कराता हूँ कि विभाग द्वारा तकनीकि रूप से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई। वहीं जिला पंचायत के अधिकारी सूत्रों के अनुसार यह तो बताते हैं कि संबंधित भ्रष्टाचारी अधिकारी की फाईल जिला पंचायत से आगे बढ़ा दी गई है अब कार्यवाही करना उच्चाधिकारियों का काम है।

इनका कहना है -

इस संबंध में शासन के जो निर्धारित मापदंड हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही चल रही है।"

-प्रफुल्ल मिश्रा
जिला अध्यक्ष भाजपा मण्डला

जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रैप में पकड़े गए अधिकारी का पद पर बने रहकर कार्य करना अत्यंत निंदनीय है।

-इंजी. कमलेश तेकाम
उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष, स्थाई शिक्षा समिति
जिला पंचायत मण्डला

मध्यप्रदेश शासन के नियम अनुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगने पर 48 घंटे में निलंबन आवश्यक है, किंतु संबंधित मामले में कार्रवाई न होना गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी शीघ्र ही इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी।

-डॉ. अशोक मर्सकोले
जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी मण्डला

भुआ रैयत के किसानों की सिंचित भूमि को राजस्व विभाग की त्रुटि ने असिंचित दिखाया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ मण्डला/भुआबिछिया

ई उपार्जन खरीफ फसल धान पंजीयन में सिंचित रकबा असिंचित दिख रहा है और किसानों ने मजबूरी बस पंजीयन कराया किसानों की सिंचित भूमि अधिग्रहण कर असिंचित भुमि का मुआवजा बनाया गया है जिसे किसानों ने लेने से मना कर दिया। ज्ञातव्य है कि एन एच 30 से सरही मार्ग राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली के तीसरे गेट रही गेट पहुंच मार्ग निर्माणधीन है जिसमें शासन ने हम किसानों की वेशकीमती सिचित कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है और अब कृषकों को असिंचित भूमि का का मुआवजा दिया जा रहा जो कि किसानो के साथ घोर अन्याय है किसानों ने असिंचित भूमि का मुआवजा लेने से इंकार किया। उक्त समस्याओ के समाधान हेतु आज भुआ बिछिया में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में जनसुनवाई में उपस्थित होकर किसानों ने अपना पक्ष रखा जिसमें एस डी एम मैडम ने शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। किसानों की ओर से राजेन्द्र कुमार साहू, रत्नेश यादव, पुर्व पार्षद प्रेमवती, दैवा उयके, नंद कुमार नंदा, गणेश महेश उयके, जमुना यादव, साकेत तिवारी, राजकुमार उयके, लल्ला यादव, दुर्गा सोनी, टीकाराम यादव, घनश्याम यादव, भीखसिंह आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

खबर संक्षेप

तालाब के पास खाली पड़ी हुई शासकीय भूमि लगातार चढ़ रही अतिक्रमण की भेंट

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों को कही शासकीय खाली पड़ी हुई भूमि नजर आती है तो वह उस पर अपनी छोटी छोटी टपरिया बनाते हुए उस पर कब्जा करना शुरू कर देते है, मगर प्रशासन द्वारा इस प्रकार से शुरूआती तौर के कब्जे को नजर अदांज किये जाने का परिणाम यह होता है कि जहां शासकीय भूमि गायब हो जाती है और जब उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया जाता है तो फिर काफी समय बीत चुका होता है जिसके चलते अतिक्रमणकारियों का बचाव करने के लिए अनेक प्रभावशाली लोग खड़े हुये नजर आने लगते है इस स्थिति में प्रशासन शासकीय भूमियों को खाली कराने में अपने हाथ डालने में असफल होने लगता है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय नगर के कालेज के समीप वायपास मार्ग तालाब के किनारे खाली पड़ी हुई शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण होते हुये देखा जा रहा है, मगर प्रशासन द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नही दिये जाने का परिणाम है कि अतिक्रमणकारी रातो रात इस भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए वहां पर अपनी दुकाने खड़ी करने से नही चूक रहे है, इस प्रकार से अतिक्रमण की भेंट चड़ रही इस भूमि के चलते जहां तालाब की सुन्दरता को ग्रहण तो लग ही रहा है साथ ही साथ यातायात में भी लोगों को परेशानियों का सामना करते हुए देखा जा रहा है, यदि प्रशासन द्वारा समय रहते हुये इस ओर ध्यान नही दिया गया तो निश्चित ही यह भूमि चंद दिनों में परेशानी का कारण बनने से नही चूक पायेगी..?

क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहने के बाद भी सालीचौकावासी मायूस हो रहे बस स्टेन्ड के अभाव में

चाय पान के टपरा तो खुले मैदान में खडे होकर बसों का इंतजार करना बनी मजबूरी...

हरिभूमि न्यूज/ सालीचौका

इस बात से इंकार नही किया जा सकता है कि क्षेत्र में विकास नही हो रहे है लगातार विकास की गंगा बहने के बाद भी यदि क्षेत्र की जनता छोटी छोटी जरूरतों की मुहताज होकर परेशान होते हुए देखा जावे तो निश्चित ही क्षेत्र के उन विकास कार्यो के औचित्य पर सबाल खड़े होने से नही चूक पाते है..? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय सालीचौका क्षेत्र में देखने मिल रही है। जहां एक ओर सालीचौका को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के कारण उसका दुनिया के मान चित्र में दर्जा जरूर बढ़ गया है। मगर यदि यहां पर व्यवस्थाओं की ओर गौर किया जावे तो आज भी क्षेत्र के लोग अनेक सुविधाओं को तरशते हुए देखे रहे है, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो यहां पर अनाज मंडी की व्यवस्था तो हो चुकी है। मगर वह भगवान ही भरोसे चल रही है जिसे मात्र निश्चित सीजन पर ही खुलते हुए देखा जाता है। कुछ इसी प्रकार का हाल स्थानीय रेल्वे स्टेशन का है जहां पर बड़ी रेल गाड़िया का स्टाप न होने के कारण लोगों को यदि नागपुर जाने की जरूरत होती है तो उन्हें गाडरवारा या फिर पिपरिया से रेल पकड़ने के लिये मजबूर होना पड़ता है। वही दूसरी ओर क्षेत्र के लोग जिस प्रमुख समस्या से जूझ रहे है वह प्रमुख रूप से है यहां पर बस स्टेन्ड का न होना बताया जाता है कि सालीचौका में जहां सप्ताह में दो बार बाजार लगता है वही रेल्वे स्टेशन होने के कारण यहां पर लोगों का आना जना बना रहता है। वही रेल्वे सुविधाओं की ओर गौर किया जावे तो यहां के रेल्वे स्टेशन पर भी मात्र चंद ट्रेनों का स्टाप होने के कारण क्षेत्र के अधिकांश लोगों का आना जाना बसों के माध्यम से ही होता है। वही यहां पर क्षेत्र के चारों से बसों का आगमन होता है। क्योंकि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला प्रमुख ग्राम बारहाबड़ा के लिए भी यहां से बस पहुंचती है। वही गाडरवारा से भी बसों का आना जाना होता है। इस स्थिति में सालीचौका पूर्णरूप से एक कस्बा का स्वरूप ले चुका है जिसके आस पास सैकड़ो ग्रामों के लोग प्रतिदिन सालीचौका आना जाना करते हुए अपनी अन्य जरूरी कार्य यही से निपटाते है। मगर इसके बाद भी यहां पर बस स्टेन्ड के साथ साथ यात्री प्रतिक्षालय नही होने के कारण जहां बस यात्रियों को अनेक परेशानियों का सामना करने मजबूर होना पड़ रहा है तथा दूसरी ओर नगर की यातायात व्यवसथा भी बिगड़ रही है। बताया जाता है कि निर्धारित स्थल पर बस स्टेन्ड के आभाव में बसों को हर कही रोकते हुए जहां सबारी बैठारी व उतारी जाती है। नगर परिषद का दर्जा प्राप्त सालीचौका में यात्री प्रतिक्षालय नही होने की स्थिति में बारिश का मौसम हो या फिर तेज गर्मी सहित ठंड के दिनों में बस यात्रियों को खुले मैदान में खड़े होकर बसों का इंतजार करते हुये देखा जाता है। इस दौरान भयानक स्थिति तो जब होती है तब किसी यात्री के साथ मरीज या फिर महिलाएं होती है इस स्थिति में खुले स्थानों या फिर चाय नास्ता की दुकानों पर बैठकर जब बस यात्री बसों का इंतजार करते है तो महिला बस यात्रियों को अनेक प्रकार से मनचले लोगों की छिटाकशी का सामना करने भी मजबूर होना पड़ता है...? इस प्रकार से क्षेत्र का लगातार विस्तार होने के बाद भी आज तक क्षेत्र की लोगों को यात्री प्रतिक्षालय की व्यवस्था न हो पाना निश्चित ही विकास कार्यो पर सबाल खडें करते हुए जान पड़ रहा है? वही अब सबाल यह उठता है कि जब सालीचौका पहले से ही एक कस्बा के रूप में स्थापित हो चुका है और जहां पर शासन द्वारा शासकीय चिकित्सालय से लेकर पुलिस चौकी व बैकों के साथ बिजली आफिस सहित हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल तक स्थापित किये गये है तो फिर आखिर में आज तक यहां पर निश्चित जगह बस स्टेन्ड व यात्री प्रतिक्षालय क्यों नही बनाया गया है..? वही अक्सर देखा जाता है कि लगातार क्षेत्र में कोई न कोई बडे नेता के साथ साथ मंत्रियों का तक आगमन होता है और उनके द्वारा क्षेत्र विकास के लिए बड़ी बड़ी बाते करते हुए क्षेत्र की जनता की तालियों से सम्मान प्राप्त करते हुए हाथ हिलाकर चले जाते है तो सबाल यह पैदा होता है कि क्या उन नेताओं को इस क्षेत्र के लोगों की यह प्रमुख समस्या कभी नही नजर आई जिसके चलते आज भी यहां के लोग बस स्टेन्ड व यात्री प्रतिक्षालय के आभाव में परेशान होते हुए देखे जा रहे है..? क्योंकि बस स्टेन्ड न होने की स्थिति में बसों के सड़को पर खड़े होने के कारण जहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वही यात्री प्रतिक्षालय के आभाव में बस यात्री गर्मी हो या फिर बारिश के दिनों में उन्हें बैठने के लिए उचित व्यवस्था खोजना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि वह अपने बैठने के लिए छायादार जगह खोजने पर भी नही मिल पाती है तो वह किसी चाय नास्ता दुकान की शरण में जाते है तो उन्हें मजबूरी बस उन्हें उस दुकान से चाय नास्ता करने मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हर दुकान पर लिखा होता है कि यहां पर फालतू बैठना मना है? इस स्थिति में यात्री मजबूरी बस अपनी जेब को हल्का करते हुए दुकानदार की नजर में फालतू नही होना चाहता? वही जब हमारी टीम ने एक वाहन मालिक से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि यहॉ बस स्टेड की कमी हम सभी वाहन संचालको को हमेशा से खलती आ रही है हम भी चाहते है कि सीलचौका मे एक बस स्टेड का होना अत्ति आवश्यक है। मगर आज तक इस ओर शायद किसी भी जिम्मेदारों द्वारा ध्यान तक देना उचित नही समझा गया है।

एक गुरू की अनोखी पहल, बीमार छात्र के घर पहुंचाई गई शिक्षा

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

हमारे शास्त्रों में जिस तरह गुरू की गरीमा का जिस तरह से बखान किया गया है उसके चलते गुरू को भगवान से बढ़ा दर्जा इसलिये दिया गया है। क्योंकि गुरू अपने शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार से शिक्षा प्रदान करने में कसर नही छोड़ता है। इस तरह गुरू की गरिमा की सच्चाई यहां पर देखने मिली रही है जहां अपने बीमार क्षेत्र को गुरू द्वारा उसके घर तक शिक्षा पहुंचाने में कोई कसर नही छोड़ रहे है। बताया जाता है कि जनपद पंचायत सांईखेड़ा के अंतर्गत आने वाले जनशिक्षा केंद्र बम्होरी कला अंतर्गत एक छोटे से गांव उसराय में शिक्षक विभिन्न नवाचारों को अपना कर विद्यार्थियों को शिक्षा में निपुण बनाने में जुटे हैं। बात नवाचारों की करें तो शिक्षा में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया और प्रयोग है जिसे अपनाकर विद्यार्थियों में अपेक्षित और सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। इसी दिशा में शिक्षक हल्के वीर पटेल ने एक नवाचार किया है। बताया जाता है कि इनकी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र विगत कई दिनों से बीमारी के चलते स्कूल नही पहुंच पा रहा है। वही छात्र के अभिभावक मजदूर वर्ग से होने के चलते यहां वहां से पैसे जुटाकर उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया है। इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे छात्र के घर जब शिक्षक पहुंचे तो अभिभावक अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित दिखाई दिये। गुरू ने अपने शिष्य को मदद करने का भरोसा देने के साथ पढ़ाई से वंचित न रह पाये इस सोच के चलते शिक्षक द्वारा छात्र के घर में ही दीवारों पर रोचक और आकर्षक ढंग से चित्रकारी करते हुए कुछ जरूरी शैक्षिक कंटेंट लिख डाले। इसके पीछे गुरू की सोच है कि अपने शिष्य को बगैर परिश्रम किये हुये ही रोचक और आनंददाई शिक्षा मिल सके। वही गुरू यानि की शिक्षक ने लंबा समय छात्र के साथ व्यतीत किया। एक शिक्षक की अपने छात्र के प्रति सकारात्मक माहौल निर्मित करने के कारण छात्र में प्रबलता व नवचेतना का विकास हुआ और शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि होते हुये देखने मिली।

बेटरी वाली स्कूटी में अचानक आग लगने से फैली सनसनी

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। लगातार बढ़ रही मंहगाई तथा पेट्रोल कीमतों से निजात पाने के लिये जहां लोगों का रूझान बेटरी से चलने वाले वाहनों की ओर अधिक बढ़ते हुये देखा जा रहा है। इस तरह बेटरी वाले वाहनों की मांग बढ़ने के चलते नगर में स्कूटी सहित अन्य वाहनों के लगातार शोरूप सजते हुये देखे जा रहे है। मगर बीते हुये मंगलवार को जिस प्रकार से लोगों ने बेटरी से चलने वाली एक स्कूटी को खड़े खड़े ही अचानक आग लगते हुये देखा तो लोग हैरत में पढ़ गये। बताया जाता है कि नगर के पलोटन गंज में एक जाने वाले डाक्टर साहब ने अपनी बेटरी से चलने वाले स्कूटी को लाकर अपनी क्लीनिक के सामने खड़ा करते हुये वह अपने काम में लग गये और स्कूटी में अचानक आग लगने के कारण मौजूद लोगों द्वारा बड़ी ही मुश्किलों के बीच आग पर पानी डालते हुये बुझा तो दिया गया। मगर इस दौरान स्कूटी काफी हद तक चल चुकी थी। इस तरह अचानक स्कूटी में आग लगने की घटना को देखते हुये पलोटन गंज क्षेत्र में सनसनी का महौल निर्मित होने से नही चूक पाया था।

पत्थर से मारपीट करते हुये चोट पहुंचाई

गाडरवारा। समीपस्थ डोगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम पापरा निवासी एक युवक द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि बीते हुये दिवस हमारे गांव के स्कूल के पास दुर्गा मूर्ति की स्थापना की तैयारिया की जा रही थी। उसी दौरान गांव का मुकेश ठाकुर व रेवाराव यादव आपस में झगडा कर रहे थें। इस पर प्रार्थी द्वारा जब दोनों को धार्मिक आयोजन के दौरान झगड़ा करने से रोका गया तो रेवाराम यादव द्वारा प्रार्थी को गालिया देते हुये पत्थर से मारपीट कर चोटे पहुंचाई।

राज्य स्तरीय शालेय व्हालीबॉल प्रतियोगिता में दूसरे दिन खिलाड़ी टीमों ने जीतने के लिये लगाया जोर, खेलों के मुहाकुंभ का आनंद लेने उमड़ रही भीड़

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा

नगर के पुराने कालेज खेल मैदान पर चल रहे 69 वी राज्य स्तरीय शालेय व्हालीबॉल प्रतियोगिता में जहां दर्शको की भीड़ उमड़ते हुये देखी जा रही है। वही आयोजन के दूसरे दिवस यानि की कल मंगलवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन 19 आयु वर्ग बालक/बालिका वर्ग के विभिन्न मैच खेले गये जिनमें शामिल खिलाड़ियों द्वारा अपनी अपनी टीमों को जीत हालिस करने के लिये खेलों का शानदार प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि आयोजन के दूसरे दिन हुए मैचों को लेकर प्रचार प्रसार समिति सदस्य मधुसूदन पटैल ने जानकारी देते हुये बताया कि मंगलवार को बालक वर्ग के मैचो में इंदौर संभाग ने जनजातीय कार्य विभाग को 2-1 से पराजित किया। वही जबलपुर ने शहडोल को 2-0 तो भोपाल ने नर्मदापुरम को 2-0 से तथा रीवा ने सागर को 2-0 से पराजित करते हुये जीत हासिल की गई। इसी प्रकार बालिका वर्ग के मैचों में उज्जैन संभाग ने सागर को 2-0 से तथा जबलपुर ने शहडोल को 2-0 व भोपाल ने नर्मदापुरम को 2-0 एवं जनजातीय कार्य विभाग टीम ने इंदौर संभाग को 2-0 से हराया गया। वही समाचार लिखे जाने तक खेल मैदान पर अलग अलग टीमों के खेल जारी थे। दूसरे दिवस के मैच शुरू होने के पूर्व रोटरी क्लब के सदस्यों एवं राव अनुज प्रताप सिंह सहित सुरेश श्रीवास्तव, घनश्याम राजपूत, राव संदीप सिंह, रीतेश राय, शुभम राजपूत ने खेल मैदान पर पहुंचकर बाहर से आयी हुई टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुये खेलों की शुरूआत कराई गई। इस दौरान आयोजन में पधारे हुये अतिथियों का स्वागत स्वागत समिति के अध्यक्ष प्राचार्य सुशील शर्मा, मनीष शंकर तिवारी, राजेश गुप्ता सहित अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के संरक्षक मिनेन्द्र डागा, अध्यक्ष सुरेन्द्र साहू, अमित पटैल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। वही राव अनुज प्रताप सिंह ने कहा कि संभागों से आये खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दी जा रही है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में पधारी हुई टीमें मेहमान है मेहमानों के स्वागत में किसी तरह से कोई कसर नही छेड़ी जावेगी। वही बताया जाता है कि इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिये बालक एवं बालिका वर्ग के ग्रुप ए मे उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल तथा ग्रुप बी मे नर्मदापुरम, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जनजातीय कार्य विभाग की टीमों को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता के आयोजन की व्यवस्थाओ मे स्वागत समिति, परिवहन समिति, क्रीड़ागन व्यवस्था समिति, भोजन व्यवस्था समिति, जल वितरण समिति, चिकित्सा समिति, प्रचार प्रसार समिति, दस्तावेज सत्यापन समिति, कंट्रोल रूम समिति सहित विभिन्न समितियों का सहयोग मिल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी संदीप नेमा के सतत मार्ग दर्शन मे आयोजन की संपूर्ण व्यवस्थाये बनाने में सहायक संचालक सीमा डोंगरे, नीलम मरावी, जिला क्रीड़ा अधिकारी के आलवा,प्राचार्य प्रतुल इंदुरख्या, एस के मिश्रा, सुनीता पटैल, जय मोहन शर्मा, सुशील शर्मा, लेखा कौरव, सतीश नाईक, संजय सोनी, विनय शंकर शर्मा, बीआरसी डी के पटैल, संदीप स्थापक, मनीष कटारे,पवन राजोरिया, सिराज अहमद सिद्धिकी, संदीप मेहरा, सत्यम ताम्रकार, बुलंद कुशवाहा, के के दुबे, चंद्रकांत साहू, स्वाति चौहान, अर्पणा ब्राउन, अर्चना नामदेव, ज्योत्सना दुबे सहित पीटीआई मुकेश पटैल, विक्रम शर्मा, अजय सोनी, आरिज खान, रोहित वाल्मीक सहित शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी जुटे हुये देखे जा रहे है।

गुपचुप तरीके हुई स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत विरोध करने वालों की चुप्पी ने खड़े किये सवाल

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में जब स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की गई थी तो कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों द्वारा इन मीटरों में अनेक प्रकार की विसंगति बताते हुये विरोध करने की शुरूआत की गई थी। वही दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों द्वारा इन मीटरों की खपत की गुणवत्ता पर सबाल उठाते हुये कहा गया था कि यह मीटर कम खपत होने के बाद भी अधिक खपत बताते है...? वही इस बात को लेकर प्रदेश के हर शहर में लगातार विरोध होते हुये देखा जा रहा था। वही दूसरी ओर अनेक महानगरों में इन मीटरों का विरोध होने की खबरे अखबारों की सुर्खिया बनने से नही चूक पा रही थी। स्थानीय स्तर पर भी बीते हुये अगस्त माह को कांग्रेस कमेटी द्वारा भी इन स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हुये ज्ञापन सौपते हुये सरकार के इस निर्णय पर अपना विरोध जताते हुये कहा गया था कि नगर में इन मीटरों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किया जावेगा। शायद इसी के चलते बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की गति को कुछ विराम दे दिया गया था। मगर नगर में जिस तरह चुपचाप तरीके से स्मार्ट मीटरों के लगाने की शुरूआत होने के बाद भी विज्ञापन वीरों द्वारा चुप्पी साधी जा रही है वह चर्चा का विषय बनने के साथ साथ इस बात की ओर संकेत देने से नही चूक रही है कि शायद स्मार्ट मीटर के निर्णय को उनके द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है..? सही मायने में देखा जावे तो इन मीटरों का विरोध करते हुये ज्ञापन देने के नाम पर सोशल मीडिया सहित अखबारों की सुर्खियों में छाने का प्रयास करते हुये अपने आपकों विधायक बनने का सपना संजोने वाले जहां उपहारों की चकाचौध में मग्न दिखाई दे रहे है..। वही दूसरी ओर नगर में इन स्मार्ट मीटरों को लगाने की शुरूआत हो चुकी है। बताया जाता है कि बाहर से आई हुई एक टीम द्वारा नगर में विद्युत उपभोक्ताओं के

घरों में लगे हुये पुराने मीटर निकालते हुये स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत शहर के यशोदा नगर से की गई है। इस संबंध में जब मीटर लगाने वाली टीम से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि नगर में लगभग सभी उपभोक्ताओं के मीटर बदलते हुये यह स्मार्ट मीटर लगाये जावेगे। वही जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा यह मीटर लगाये जा रहे है इनका कही किसी के द्वारा विरोध नही किया जा रहा है। इस संबंध में मीटर लगाने वाली टीम द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी तक किसी के द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वैसे भी देखा जावे तो सभी उपभोक्ताओं के घरों के बाहर मीटर लगे हुये है हम जाते है चुपचाप पुराना मीटर निकालते हुये चंद मिनिट के अंदर नया स्मार्ट मीटर लगाते हुये चलते बनते है। इस तरह नगर में न तो इन स्मार्ट मीटरों का उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है और न ही किसी राजनैतिक पार्टी के लोगों द्वारा जिसके चलते मीटर लगाने की शुरूआत कर दी गई और कुछ दिनों के अंदर नगर में सभी उपभोक्ताओं के यहां पर इन स्मार्ट मीटरों को स्थापित कर दिया जावेगा। इन मीटरों के लगने से बिजली विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधा हो जावेगी यदि किसी के यहां पर बिजली बिल समय पर नही भरा जाता है तो बिजली विभाग के आफिस से ही उसकी बिजली लाईन काट दी जावेगी..? अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि जिस तरह मीटर लगाने वाली टीम द्वारा बताया जा रहा है कि नगर में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरूआत की गई है और कही किसी भी प्रकार से कोई विरोध नही हो रहा है..। इस सच्चाई को लेकर तो यही बात उजागर हो रही है कि जिन लोगों द्वारा बीते हुये अगस्त माह में इन स्मार्ट मीटरों की सच्चाई पर संदेह व्यक्त करते हुये ज्ञापन देते हुये विरोध किया जा रहा था वह सिर्फ सोशल मीडिया व अखबारों की सुर्खियों में छाते हुये अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में जुटे रहते हुये अब उनके द्वारा भी इन स्मार्ट मीटरों को स्वीकार कर लिया गया है...? खैर सच्चाई जो भी हो उसे तो भगवान ही जाने। मगर नगर में उपभोक्ताओं सहित विरोधी राजनैतिक पार्टियों के बगैर किसी विरोध के स्मार्ट मीटरों के लगाने की शुरूआत हो चुकी है।

रूह कंपाने वाली महंगाई में घटी इत्र की पूछ परख

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। हर वर्ष देखा जाता है कि दीपावली के त्यौहार के पहले कन्नौज से युवा इत्रफरोशों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था जो बीते हुये लगभग तीन महिनों से नगर सहित क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हुये अपना इत्र विक्रय करते हुये देखे जा रहे है। इन इत्र बेचने वाले युवाओं की खूब सूरत पेटियो में गुलाब, केवडा, चमेली, नाग चम्पा, मुश्क, हिना के इत्र के कंटर सजे रहते है तथा ये ग्राहको की मनुहार कर उन्हे इत्र बेच जीविका चलाते है। मगर इत्र का धंधा करने कन्नौज से निकले व्यापारियों द्वारा बताया कि उनके पूर्वज पहले दीपावली के पहले गाडरवारा में मुकाम कर व्यापारियो, सम्पन्नो, मध्यमवर्गीय लोगो को इत्र बेचा करते थे और अच्छा धंधा कर बाखुशी कन्नौज वापिस हो जाते थे, अपने पूर्वजो की परम्परा के अनुसार अब वे भी इत्र बेचने शहर में आए है। किन्तु अब इत्रो की पहले जैसी पूछ परख न रहने से उनका धंधा कमजोर चल रहा है, उन्होने बताया कि खंदली इत्र खरीदने की जहां रूह कँपाने वाली महँगाई में लोगों की हिम्मत नही रह गयी है।

खबर संक्षेप

मेहंदवानी आईटीआई भवन निर्माण में मजदूर की मौत पर कार्यपालन यंत्री पीआईयू और ठेकेदार को नोटिस

डिंडोरी। विकासखंड मेहंदवानी स्थित आईटीआई भवन निर्माण में मजदूर की मौत के मामले में कार्यपालन यंत्री, पीआईयू पारस सिंह को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जो गंभीर लापरवाही है। इसके लिए पारस सिंह के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाऐगी। वहीं इस मामले में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मजदूर की मौत होने पर ठेकेदार मेसर्स हरगोविंद दास गुप्ता को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

नवागत कलेक्टर के सामने जनसुनवाई में उमड़ी ग्रामीणों की भीड़, 78 आवेदनों पर त्वरित निर्देश

डिंडोरी। जिले की नव नियुक्त कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्रामीणों का भरोसा झलकता नजर आया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और कहा कि अब हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा।

जनसुनवाई में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए नागरिकों ने कुल 78 आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए, वहीं जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव नहीं था, उनमें समय-सीमा निर्धारित कर संबंधित विभागों को जांच व कार्रवाई के आदेश दिए गए।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर आवेदन की गंभीरता से जांच कर पारदर्शी एवं नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई में ग्राम हर्रा पिण्डरुखी की राधाबाई बनवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति के बावजूद एक व्यक्ति द्वारा रिश्वत मांगने और मारपीट करने की शिकायत करते हुए प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की। ग्राम मिगड़ी की मनीषा बाई ने आवास योजना में अनियमितता की शिकायत करते हुए बताया कि पक्के मकान वालों को लाभ, जबकि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वंचित रह गए हैं। जनपद पंचायत मेहदवानी के पूर्व सरपंचों ने 2014 से 2022 तक के लंबित मानदेय भुगतान की मांग की। ग्राम बजाग के किसानों ने धान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की, क्योंकि खसरा अद्यतन और सर्वेयर की त्रुटियों के कारण कई किसान वंचित रह गए। ग्राम कुडा के महेंद्र प्रसाद और मंगल प्रसाद ने राज्य मार्ग चौड़ीकरण में मुआवजा विसंगति का मुद्दा उठाया।ग्राम पंचायत देवरी माल के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पुशवा लाल बैगा के घर तक सड़क निर्माण की मांग की।

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने दो टूक कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि आवेदनों पर समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई करें।इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जेपी यादव, एसडीएम सुश्री भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के किसानों ने की मांग: प्रति हेक्टेयर धान खरीदी सीमा 22 से बढ़ाकर 44 क्विंटल किए जाने का हो प्रावधान

डिंडौरी।

जिले के किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि वर्तमान में डिंडौरी जिले में प्रति हेक्टेयर केवल 22 क्विंटल धान उपार्जन का मान्य पंजीयन किया जा रहा है, जबकि किसान मेहनत से प्रति हेक्टेयर 45 से 50 क्विंटल तक धान का उत्पादन कर रहे हैं।किसानों ने कहा कि इस सीमा के कारण अधिकांश धान समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पा रहा है और उन्हें मजबूरन खुले बाजार या निजी व्यापारियों को कम दामों पर अनाज बेचना पड़ता है, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि पड़ोसी जिला मंडला में प्रति हेक्टेयर 44 क्विंटल तक धान खरीदी की अनुमति है, जबकि डिंडौरी में यह सीमा अभी भी 22 क्विंटल तक सीमित है। यह असमानता किसानों के लिए अन्यायपूर्ण है।किसानों ने कहा कि पिछले वर्ष भी उन्होंने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था, परंतु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

किसानों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगों को उच्च स्तर पर रखने की अपील की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही प्रति हेक्टेयर धान खरीदी सीमा 40 से 45 क्विंटल तक नहीं बढ़ाई गई, तो वे आगामी दिनों में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने इस स्थिति की समूची जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर होने की बात कही है।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते,किसान भोलेराम ठाकुर, कामता ठाकर, रतन सिंह ठाकुर सहित दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान मौजूद रहे हैं।

हानिकारक सब्जी उत्पादन पर कलेक्टर सख्त, दोषियों पर होगी वैधानिक कार्यवाही

डिंडोरी। सब्जी उत्पादन में बाहर प्रदेश से आए हुए किसानों द्वारा रासायनिक और जहरीली दवाओं का उपयोग करने का मामला जोर पकड़ रहा है। इस पर जिला कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सख्त कार्यवाही के संकेत दिए है। पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हानिकारक सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की वैधानिक जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसानों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में बड़ी मात्रा में रसायनिक खाद का उपयोग कर सब्जी का उत्पादन करने वाले बाहरी प्रदेश के कारोबारियों का प्रकोप जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे प्रदेश से आकर इन कारोबारियों ने जिले की कम उपजाऊ जमीन सस्ती कीमत पर खरीद कर रसायनों का बेजा उपयोग कर बड़ी मात्रा में सब्जी का उत्पाद शुरू किया है। जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके द्वारा बड़ी मात्रा में रसायनों का उपयोग किए जाने से सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन ये सब्जियां मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकती है। इनके द्वारा उत्पादित की जा रही सब्जियों में किस मात्रा में रसायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा कभी भी कोई पड़ताल नहीं की गई। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इन सब्जियों से जिले का आम आदमी का स्वास्थ प्रभावित हो सकता है लेकिन इसको लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से लापरवाह है। जिससे निश्चित होकर मनमाने तरीके से रसायनों का उपयोग कर खतरनाक सब्जियों की खुलेआम

खेती कर रहे है। जानकारी के अनुसार सब्जी उत्पादन करने वाले किसान ज्यादा कमाई करने के लिए जहां इंसानों को सब्जी के साथ जहर बेच रहे वहीं इन हानिकारक रासायनिक खादों का उपयोग कर जमीन की उवर्रा शक्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। एनपीके उवर्रक का इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकता है खासकर जब इसे अधिक मात्रा में निगला जाये या इसके संपर्क में आया जाये जिससे विषाक्त हो सकती है साथ ही इसके उपयोग से मिट्टी और सब्जियों में मौजूद सूक्ष्म जीवों के लिए भी घातक होता है। इसके उपयोग से सब्जियों में लगने वाले कीड़े नष्ट होते हैं और सब्जी में ही रह जाते हैं जिसका उपयोग इंसान कर रहे है। वहीं इनके द्वारा सेलेक्ट बोरान खाद का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसका सब्जी का उपयोग करने वाले मनुष्यों पर बुरा प्रभाव पडने की पूरी संभावना रहती है। जिसके निरंतर उपयोग से पेट, आंत, याकृत, गुर्दे और मस्तिष्क पर असर पडता है, और अतंतः मृत्यु भी हो सकती है। जानकारों की माने तो प्रतिदिन 20 मिलीग्राम से अधिक खुराक लेने से पुरूषों में प्रजनन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसके अलावा विषाक्तता के लक्षणों के साथ चिड़चिड़ापन कंपकंपी, कमजोरी, सिरदर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण भी शामिल हैं। इसके साथ ही उत्पादकों द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी तादाद में उपयोग किया जा रहा है जिसके संपर्क में आने से इंसानों पर कई विपरीत प्रभाव पड सकते हैं जैसे कि सांस लेने पर खांसी, और गले में खराश, निगलने पर आंतरिक जलन या मतली और त्वचा पर लालिमा और खुजली। लंबे समय तक या बार-बार संपर्क में रहने से त्वचा की समस्या और बढ़ सकती हैं। बावजूद इसके सब्जी उत्पादक द्वारा इनका भरपूर उपयोग किया जा रहा है और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन कलेक्टर के द्वारा सक्त कार्रवाई के संकेत दिये गये हैं

नगरीय निकायों में दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों पर सख्त रोक, 25 अक्टूबर तक मांगी गई पूरी रिपोर्ट

शहपुरा। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3788/3833019/2025/18-1, दिनांक 8 अक्टूबर 2025 ने प्रदेशभर के नगरीय निकायों, नगर परिषदों और नगर निगमों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर खलबली मचा दी है।शासन ने सभी निकायों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दैनिक वेतन पर किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति या कार्य पर रखने की अनुमति नहीं है, और यदि पिछले वर्षों में ऐसी नियुक्तियां की गई हैं तो उनका पूरा ब्यौरा 25 अक्टूबर 2025 तक मंत्रालय को भेजा जाए।

शासन ने मांगी पूरी जानकारी रिपोर्ट तय प्रारूप में भेजने के निर्देश

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 656/527/2000/सी/वार दिनांक 28.03.2000 में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी निकाय, निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण या सहकारी संस्था में दैनिक वेतन पर नियुक्ति प्रतिबंधित है।फिर भी कई नगरीय निकायों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया है, जो शासन की नीति के विपरीत है। इस पर मंत्रालय ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि प्रत्येक नगर निकाय 28 मार्च 2000 के बाद की गई सभी दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियों की सूची तैयार करे और उसे निर्धारित प्रारूप में शासन को भेजे।रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम, नियुक्ति तिथि, वर्तमान पदस्थापना, संबंधित अधिकारी का नाम, और नियुक्ति के संबंध में प्राप्त स्वीकृति का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया

है।शासन के इस आदेश के बाद शहपुरा नगर परिषद में तेज हलचल देखी जा रही है।नगर परिषद में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मी, जल विभाग सहायक और अन्य श्रमिक अब अपने भविष्य को लेकर गंभीर असमंजस में हैं।कर्मचारियों ने बताया कि वे वर्षों से नगर की सफाई, जलापूर्ति और अन्य जनसेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन अब शासन के इस आदेश से उनकी नौकरी पर संकट मंडरा गया है।

एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक ने कहा — "हमने कोरोना काल में भी काम बंद नहीं किया। सड़कों पर सफाई की, नगर को सुरक्षित रखा, लेकिन अब सरकार ने हमें एक झटके में बाहर कर दिया। हमारे परिवार का भविष्य अधर में लटक गया है।"वहीं नगर परिषद के जल विभाग के एक कर्मचारी ने कहा कि यह आदेश प्रशासनिक रूप से भले जरूरी हो, लेकिन इससे गरीब तबके की रोटी पर सीधा असर पड़ेगा।

शहपुरा नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि आदेश सीधे नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल से आया है और इसका पालन अनिवार्य है। "विभाग से निर्देश मिला है कि 28 मार्च 2000 के बाद नियुक्त सभी दैनिक वेतनभोगियों की जानकारी एकत्र की जाए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के लिए है।" हालांकि अधिकारी यह भी मानते हैं कि यह निर्णय जमीन पर कई सामाजिक और मानवीय चुनौतियाँ खड़ी करेगा।शासन के इस आदेश को लेकर प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के योगदान को देखते हुए सरकार को उनके पुनर्वास या संविदा रूपांतरण की नीति भी बनानी चाहिए।बिना वैकल्पिक व्यवस्था के यह फैसला हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डालेगा। शासन का आदेश निकायों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सही दिशा में कदम माना जा रहा है, लेकिन शहपुरा जैसे छोटे नगरों में यह फैसला कई परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट बनकर उभरा है। अब देखना होगा कि सरकार इसके मानवीय पहलू पर क्या रुख अपनाती है।

स्कूल के बच्चों ने उठाया विकास का मुद्दा, कलेक्टर से मांगी पक्की सड़क

डिंडौरी। विकासखंड करंजिया के अंतर्गत आने वाले बैशाखू टोला गाँव के स्कूली बच्चों ने पहल करते हुए प्रशासन का ध्यान अपने गाँव की जर्जर सड़क की ओर खींचा है। चुनपथरी तक पक्की सड़क की मांग को लेकर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और सड़क निर्माण की गुहार लगाई। ग्रामवासियों ने बताया कि बैशाखू टोला से मुख्य सड़क तक पहुँचने का कोई पक्का मार्ग नहीं है। बरसात में रास्ता कीचड़ और

पानी से भर जाता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांदीपनि विद्यालय मोहतरा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को कीचड़, गढढे, वाले मार्ग से आना- जाना पडता है, जिससे परेषानी पेष आती है। और कई दफा स्कूल बच्चे हादसों का षिकार भी होते है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जहाँ लगभग सभी गाँवों तक सड़कें पहुँच चुकी हैं, वहीं उनका टोला अब भी उपेक्षित है। कई बार ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामवासियों ने बताया कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच पाती, जिससे समय पर इलाज न मिल पाने की गंभीर स्थिति बन जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण करें और जल्द से जल्द बैशाखू टोला से चुनपथरी तक सीसी रोड निर्माण की दिशा में कार्यवाही करें। गौरतलब है कि विगत दिनों स्कूली बच्चों को हो रही परेषानी के चलते अमरकंटक डिंडौरी मार्ग में उतरकर प्रदर्षन भी किया था। हालांकि समझाइश के बाद बच्चों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। लेकिन बच्चों की मांग है कि उनके और ग्रामीणों के आवागमन के लिए व्यवस्थित मार्ग का निर्माण किया जाये। ताकि उन्हें परेशानी से निजात मिल सके।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा दीपावली पूर्व खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण जारी

डिंडौरी। आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिलेभर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण एवं खाद्य सामग्री के नमूनों का संग्रहण कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को तहसील क्षेत्र बजाग में विभिन्न होटल एवं दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नामदेव बेकरी से मिल्क केक, पवित्र भोजनालय से अरहर दाल, पनीर एवं सांभर, तथा न्यू मित्र मिलन ढाबा से एनर्जी ड्रिंक एवं आटे के नमूने संग्रहित किए गए। इसके साथ ही शुभ किराना स्टोर, विनोद कुमार साहू किराना स्टोर एवं अन्य दुकानों का निरीक्षण कर एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण कराया गया। 13 अक्टूबर 2025 को डिंडोरी नगर स्थित रितु स्वीट्स एवं भोजनालय में सघन निरीक्षण कर खोवा, छेना एवं नमकीन के नमूने लिए गए। इसके अतिरिक्त मां शारदा ट्रेडर्स से सरसों तेल, बिस्कुट एवं राइस ब्रान तेल के नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। अभिहित अधिकारी मनोज पाण्डेय ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए यह कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह टेकाम एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।

जनपद पंचायत करंजिया में हुई समीक्षा बैठक

श्रमिक नियोजन बढ़ाने, अपूर्ण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश

डिंडौरी (करंजिया)। जनपद पंचायत करंजिया में आयोजित समीक्षा बैठक में नवागत सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन बढ़ाने और अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

'एक बगिया मां के नाम' अभियान की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए श्री चौधरी ने इसमें गति लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी सचिवों और जीआरएस (ग्राम रोजगार सहायक) को निर्देशित किया कि अपूर्ण आवासों को शीघ्रता से पूर्ण कराएं और लाभार्थियों से संपर्क कर योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करें।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विकासखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना को अपूर्ण कार्यों की जानकारी नहीं होती है, तो उनके विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सीईओ ने बीईओ और बीआरसी को निर्देशित किया कि सभी शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत

उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने तथा विद्यालयों में साफ-सफाई विशेष रूप से शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने पर भी बल दिया बैठक के बाद श्री चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बीएमओ को केंद्र में समुचित स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध दवाओं और स्टॉक का भी अवलोकन किया।इसके अतिरिक्त, नव-निर्मित पंचायत भवन मोहतरा का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए गए।जनपद पंचायत सीईओ अक्षय डिग्रसे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राम मिलन रावत, सहायक यंत्री मनरेगा कशिश नायक, बीएमओ, बीईओ, बीआरसी, विभिन्न विभागों के योजना प्रभारी, सचिव, जीआरएस, मोबिलाइजर एवं पीसीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला किसान दिवस समारोह, भोपाल में डिंडौरी जिले की सहभागिता

डिंडौरी । 15 अक्टूबर 2025 रवींद्र भवन, भोपाल में महिला किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, वानिकी, उद्यमिता एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महिला किसानों की भूमिका को सम्मानित करना और उनके अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर डिंडौरी जिले की 50 महिला किसान दीदियां कार्यक्रम में सहभागिता कर रही हैं। वे जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए भोपाल रवाना हुई हैं। डिंडौरी से प्रतिभागियों को रवाना करते समय कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसआरएलएम की जिला परियोजना प्रबंधक श्रीमती अपर्णा पांडेय तथा प्रदान संस्था की टीम उपस्थित रही। उन्होंने सभी प्रतिभागी बहनों को शुभकामनाएँ दीं और उनके उत्साहवर्धन हेतु प्रेरक संबोधन दिया।

स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

अमरपुर। शासकीय महाविद्यालय अमरपुर में महाविद्यालय के प्राचार्य संदीप सिंह के निर्देशन और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. अनिल कुशराम के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए एसवीसीजी प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. अनिल कुशराम ने बताया कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व मानसिकता संगठन के द्वारा सर्वप्रथम 1992 में मनाया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, डिप्रेशन, स्ट्रेस, समाज में मानसिक रोगों से लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए आदि जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में डॉ. सुनील काकोड़िया के द्वारा अपने व्याख्यान में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य के जितना ही जरूरी हैं, और इसके बारे में खुलकर संवाद करना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टॉफ डॉ. सौरभ सामंत एवं छात्र - छात्राएं उपस्थित रहे।

आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स ने भी सैलरी काटने पर जताई आपत्ति

डिण्डौरी

जिले के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक और आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स सितंबर 2025 माह की सैलरी कटौती को लेकर नाराज हैं। तकनीकी खामियों के कारण दोनों ही वर्ग के प्रशिक्षकों की उपस्थिति सही ढंग से दर्ज नहीं हो सकी, जिससे वेतन में अनावश्यक कटौती हुई है।

VTS Manpower App **तकनीकी खामियों से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सैलरी प्रभावित**

नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ, डिंडौरी के अध्यक्ष ने बताया कि सितंबर माह के दौरान VTS Manpower App कई दिनों तक तकनीकी रूप से बाधित रहा। प्रशिक्षकों ने समय-समय पर उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास किया और माह के अंत में प्राचार्यों द्वारा भौतिक उपस्थिति पंजी की पुष्टि कर सही डेटा पोर्टल पर दर्ज कराया गया।इसके बावजूद, सैलरी में कटौती जारी है। महासंघ ने डी.पी.आई., व्यावसायिक शिक्षा समन्वयक, कलेक्टर डिण्डौरी और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर शीघ्र समाधान की मांग की है। प्रशिक्षकों का कहना है कि - दीपावली के समय यह कटौती अत्यंत निराशाजनक है और प्रशासन को तकनीकी खामियों के कारण उत्पन्न इस त्रुटि का तुरंत समाधान करना चाहिए।

आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की सैलरी में भी कटौती, अवकाश की अनदेखी

आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स ने बताया कि 4 सितंबर की शाम को ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का आदेश प्राप्त हुआ था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर अवकाश था। उन्होंने 6 सितंबर से लगातार उपस्थिति दर्ज की।इसके बावजूद एजुकेशन पोर्टल में 5 दिन की सैलरी काटी जा रही है, वहीं 30 सितंबर को स्थानीय शासकीय अवकाश था। उसकी भी सैलरी काटी जा रही है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स ने जिला शिक्षा अधिकारी, डिण्डौरी को पत्र भेजकर मांग की है कि सितंबर माह की पूरी सैलरी तुरंत जारी की जाए। प्रशिक्षकों का कहना है कि - दीपावली जैसे त्यौहार के समय यह कटौती अनुचित है और तकनीकी खामियों को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है।

हरिभूमि

नर्मदा भूमि

14

जबलपुर, बुधवार 15 अक्टूबर 2025

login : www.haribhoomi.com

करेली | तेंदूखेड़ा | श्रीधाम | सालीचौका | सुआतला | गाडरवारा | राजमार्ग | साईंखेड़ा | चीचली | करकबेल

वर्ष भर वसूली करने वाला खाद्य विभाग जुटा जांच में

कलेक्टर के निर्देशों का किया जा रहा पालन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

जिले मे नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री प्राप्त हो इसके लिए सरकार द्वारा खाद्य विभाग बना गया है। लेकिन जिले मे पदस्थ खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पूरे वर्ष भर दुकानदारों से वसूली करने के बाद त्यौहार पर कलेक्टर के आदेश पर जांच रूपी नौटंकी कर जांच की जाती है। त्यौहार निकलने के बाद किसी प्रकार की कोई सुध विभाग द्वारा नही ली जावेगी। खाद्य विक्रेताओं द्वारा धड़ल्ले से दूषित व मिलावटी सामग्री का विक्रय किया जावेगा। जबकि सरकार की मंशा है कि नागरिकों को जांच की हुई और साफ स्वच्छ सामग्री मिल रही होगी लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया जा रहा है।

त्योहारों मे खुलती है नींद

जिले मे पदस्थ खाद्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा केवल त्यौहार के समय उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर ही नींद खुलती है इसके अतिरिक्त साल भर तसल्ली के साथ कुम्भकर्णीय नींद मे विभाग सोता रहा है। अधिकारियों के निर्देश के उपरांत की जाने वाली कार्रवाई मे भी विभाग के जिम्मेदारों द्वारा सैंपल लेकर इति श्री कर ली जाती है और पूरे साल भर दुकानों से वसूली जारी रहती है। नगर की प्रत्येक किराना तथा मिष्ठान भंडार से खाद्य निरीक्षकों द्वारा वूसली की जाती है। इनकी सांठ गांठ इतनी मजबूत होती है कि शिकायत पर जांच के नाम पर भी लीपापोती की जाती है। जबकि सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर खाद्य सामग्री मिले तथा समय समय पर उनकी जांच हो इसके लिए विभाग बनाया गया है लेकिन विभाग वसूली मे व्यस्त रहता है।

प्रशासन करे ठोस कार्रवाई

जिले मे पदस्थ खाद्य विभाग के कर्मचारियों को प्रतिदिन टास्क देकर जांच करने के निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाने चाहिए तथा इनकी संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। किराना तथा मिष्ठान भंडार से की जाने वाली वसूली पर भी मुख्य फोकस बनाकर इनकी निगरानी की जानी चाहिए। दुकानदारों को डरा धमका कर खाद्य निरीक्षकों द्वारा की जाने वाली वसूली का परिणाम यह होता है कि दुकानदार लोगों को मिलावटी खाद्य सामग्री धड़ल्ले से विक्रय करता रहा है और उसे पूरा विश्वास होता है कि मेरी दुकान पर छापा नही पड़ेगा क्योकि खाद्य निरीक्षक से सांठगांठ है तथा उन्हे नजराना भी दिया गया है। प्रशासन को चाहिए कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई करे जिससे लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके।

15 प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे एवं श्रीमती कविता राठौर ने नरसिंहपुर, करेली व गाडरवारा में 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध डेयरी व अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दूध, दही, पनीर, मिठाई, खोवा, छैना के रसगुल्ले, सोन पपड़ी, खाद्य तेल, मसाले आदि के लगभग 41 नमूनों को संग्रहीत किया। संग्रहीत नमूनों की जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कार्यवाही के दौरान मौके पर 20 किलोग्राम चाकलेट बर्फी एवं कुंदा पेड़ा विनष्टिकरण किया गया। इस दौरान खाद्य विक्रेताओं को खाद्य सामग्री ढंककर रखने, स्वच्छता पूर्वक और गुणवत्तापूर्ण मिठाईयों का विक्रय करने के निर्देश दिए।

खबर संक्षेप

जनसुनवाई में आये 130 आवेदन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में आवेदकों ने विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 130 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उन आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया।

विश्व हाथ धुलाई दिवस पर होंगे विविध कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर 15 अक्टूबर 2025 को बच्चों, शिक्षकों एवं जन समुदाय में साबुन से हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देना व स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले की समस्त शालाओं में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर ने बताया कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर जिले की समस्त शालाओं में साबुन से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन व स्वच्छता सत्र, स्वच्छ हाथ- स्वच्छ जीवन विषय पर निबंध, चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता, साबुन से हाथ धुलाई के सरल स्टेप पोस्टर के माध्यम से दर्शायी गई प्रक्रिया के माध्यम से साबुन से हाथ धुलाई गतिविधि और शालाओं में निर्मित हाथ धुलाई इकाइयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने, आवश्यक रखरखाव व संधारण करते हुए साबुन से हाथ धुलाई की गतिविधि आयोजित की जावेंगी।

साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण आज से

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जिले के अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए साइबर अपराध से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा के संबंध में 15 से 17 अक्टूबर तक प्रशिक्षण ई- दक्ष केन्द्र नरसिंहपुर में दिया जाएगा। अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पहला बैच 15 अक्टूबर को, दूसरा बैच 16 अक्टूबर को और तीसरा बैच 17 अक्टूबर को प्रातरू 11 बजे से ई-दक्ष केन्द्र नरसिंहपुर में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर नरसिंहपुर ने विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूची के अनुसार उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अनिवार्य ता सुनिश्चित कराएं। संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति अवकाश स्थानांतरण की स्थिति में कार्यरत अन्य कर्मचारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित कर उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

विधायक की जनसुनवाई मेंआई राजस्व से संबंधित शिकायतें

तेंदूखेड़ा। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नर्मदा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी समस्याओं और आपसी मुलाकात को लेकर तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने तेंदूखेड़ा में अपने कार्यालय में ही लोगों से सीधे संवाद और समस्याओं के निराकरण की दिशा में जनसुनवाई शुरू की है। पूर्व में यह जनसुनवाई शनिवार के दिन की जाती थी लेकिन अब इसे मंगलवार के दिन शुरू किया है। शिकायतों को तत्काल प्रभाव से संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय सीमा में निराकृत करने निर्देश देकर समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन शिकायतों में सबसे ज्यादा मामलें राजस्व विभाग से संबंधित ही निकल कर सामने आ रहे हैं।

आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

गत दिवस शासन के निर्देशानुसार जिला आपदा प्रबंधन क्षमता वृद्धि एवं जनजागृति कार्यक्रम 2025-26 के तहत उच्च शिक्षण संस्थान एम.आई.एम.टी. कॉलेज में आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम संकट मोचन बल मुम्बई एवं जिला होमगार्ड बल द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीरेन्द्र सूर्यवंशी प्लाटून कमाण्डर, डॉ. अशोक कुमार गर्ग प्राचार्य एवं हवलदार सुन्दरलाल उईके की उपस्थिति में किया गया। प्राचार्य डॉ. गर्ग द्वारा आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समाज में इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता पर बल दिया तथा एन.सी.सी कैडिट्स की भूमिका को निरूपित किया। संकट मोचन बल द्वारा एन.सी.सी. के छात्र-छात्राओं को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान एन.सी.सी कैडिट्स को आकाशीय बिजली, भूकंप, आग, बाढ़, सर्पदंश, सीपीआर सहित अन्य आपदाओं से राहत एवं बचाव संबंधी तकनीकि मदद व सुझाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन मेजर डॉ. पराग नेमा एवं आभार लेफ्टि. जितेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर महाविद्यालय सहायक प्राध्यापक सुश्री शीतल जाट, कृतिका झारिया सहित बड़ी संख्या में एन.सी.सी. छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रहीं।

नगद व जेवर की लूट, पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। गत दिवस थाना क्षेत्र तेंदूखड़ा अंतर्गत आने वाले बंधा ग्राम के निवासी रामकृष्ण पटैल पिता एवं मालती बाई पत्नि द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत देकर आशीष पिता मूलचंद मेहरा निवासी बौछार थाना गोटेगॉव, शिवराज पिता मुन्ना मेहरा निवासी बंधा तह. व थाना तेंदूखेडा , राकेश उर्फ छोटू पिता अमोल मेहरा बंधा तह. व थाना तेंदूखेडा ,अमोल मेहरा पिता नथ्थे मेहरा बंधा तह. व थाना तेंदूखेडा के खिलाफ लिखित शिकायत में बताया कि इन लोगों ने जबरदस्ती आवेदक के घर से नगद राशि एवं सोने का जेवर सहित चोरी कर आवेदक गणों की पुत्री जानकी उर्फ श्रद्धा को भगाकर ले जाने तथा आवेदक गणों को बाहर से ताला लगाकर बंद करने के संबंध में बताया कि 11.10.2025 को रात्री करीब 1.30 बजे हम आवेदकगण मैं मेरी पत्नी तथा एक पुत्र रूपेश तथा मेरी पुत्री जानकी उर्फ श्रद्धा कमरे में सो रहे थे उक्त अनावेदकगण आये जबरन अलमारी में रखे नगद राशि 2,00,000 रूप्ये जो चना मसूर एवं मैस तथा पुत्री की स्कॉलरशिप के मिलाकर हुये थे जो गोदरेज में रखे हुये थे एवं जेबर सोने का करीब 2 तोला का हार, 2 तोला सोने की झुमकी 2 तोला का पैडिल रखे हुये थे तथा मोबाईल रेडमी जिसमें डली है। उक्त अनावेदक गण गुंडा गिर्दी से आये और मेरी पुत्री जानकी उर्फ श्रद्धा उम्र 19 वर्ष तथा उक्त समस्त जेबर तथा नगद राशि चोरी कर ले गये और ताला लेकर साथ में आये हम आवेदक गणों को बाहर से ताला लगाकर कमरे में बद करके चले गये हम आवेदक गण चिल्लाते रहे सुबह जब हम आवेदक गणो ने हमारे भाई को चिल्लाया तभी उन्होने ताला तोड़कर हमें

बाहर निकाला। उक्त घटना की जानकारी पुलिस थाना तेंदूखेडा जाकर रिपोर्ट लिखाई तो उन्होने मेरी पुत्री की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर दी राशि एवं जेबर चोरी की कोई रिपोर्ट में कोई जिक्र ही नही किया। जिसकी तेंदूखेडा थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी। उक्त अनावेदक गण क-3 ग्राम कोटवार है एवं सभी अनावेदक गण अनुजाति वर्ग के है जो आपराधिक प्रविति के है। मुझे आशंका है कि उक्त मेरी राशि खुर्द-बुर्द कर देगे एवं मेरी पुत्री को जान से मार सकते अनावेदक गणों पर कड़ी से कडी कार्यवाही करते हुये हमारी पुत्री को ढूंढकर उक्त नगद राशि तथा जेबर दिलाये जाएं।

36 छात्रों को निशुल्क साईकिलें वितरित

तेंदूखेड़ा

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चांवरपाठा में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत 36 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई ।साथ ही विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना के लिए संगीत सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई है ।इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर विद्यालय से दूर हैं उन्हें यह साइकिल उन्हें न केवल समय से विद्यालय पहुँचने में मदद करेगी। बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी देगी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सशक्त बनाने बेटियों को आगे बढ़ाने और युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है इस योजना से बालक और बालिकाओं दोनों को समान अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवकुमार पालीवाल सुभाष पालीवाल नेतराज पटेल राजेश अग्रवाल सहित स्कूल के प्राचार्य अध्यापक सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सर्वसुविधा युक्त कॉलोनी का शुभारंभ आज

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

जिला मुख्यालय के खैरी नाका के समीप श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल के बाजू में विकसित की जा रही अक्षरधाम डी आर जे पार्क कॉलोनी के कॉलोनाइजर अमित जायसवाल ने बताया कि हमारे द्वारा अक्षरधाम कॉलोनी विगत कुछ वर्ष पहले मुशरान भवन के समीप विकसित की गई थी जिसमें सभी सुविधाएं हमारे द्वारा टी एंड सी पी की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन करते हुए विकसित की थी जो कुछ ही वर्षों में लगभग पूर्ण विकसित हो चुकी है निवासरत लोग संतुष्ट हैं उसी क्रम में यह दूसरा फेस अक्षरधाम डी आर जे के नाम पर विकसित कर रहे हैं इसमें भी सभी जैसे, सीमेंट से बनी मोटी सड़क, सीवरेज लाइन पाइप वाली नाली, पानी पाइप लाइन, स्ट्रीट लाइट के साथ स्वयं की डी पी के साथ बिजली की सुविधा, मध्य स्थल पर मंदिर के साथ भव्य पार्क में बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह, पक्की बाउंड्री वाल से पूरी को सुरक्षित किया गया है भव्य प्रवेश के लिए एक ही द्वार बनाया गया है साथ ही मेडीटेशन प्वाइट, बेडमिटर कोर्ट, जागिग पार्क, आउटडोर जिम गजीबो, जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसमें हमारी कोशिश यही है कि सभी नियमों का पालन करते हुए जो लोग यहां निवास करे उनको कोई असुविधा न हो और न ही अपने आप को ठगा मेहसूस करे, कल 15 तारीख को कॉलोनी का शुभारंभ किया जा रहा है दीपावली के पावन पर्व पर विशेष ऑफर भी रखा गया है मात्र 51000 रुपए जमा कर अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं और इसमें विशेष छूट के साथ ढेर सारे इनाम भी पर्व पर रखे गए है। लोगों के जीवन का सपना साकार करने के लिए हम भी सहयोगी बन रहे हैं 90 प्लॉट इस कॉलोनी में बिक्री के लिए रखे गए हैं।अक्षरधाम डी. आर. जे. पार्क सर्व सुविधायुक्त आवासीय परिसर में अपने सपनों का घर बनाने के लिए पहले आयें, पहले पायें के लिए प्लाट बुक करने के लिए प्रवेश जायसवाल , अमन जायसवाल से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

चरनोई गौ बैठान कुम्हरगढा और विभिन्न मदों की भूमि के साथ शासकीय भूमि पर दबंगों का कब्जा

मारे मारे फिर रहे मवेशी

तेंदूखेड़ा। तेंदूखेड़ा तहसील क्षेत्र यदि सरकारी आंकड़े उठाकर देखें तो लगभग 44776.283 हेक्टेयर कुल भूमि है। जिसमें शासकीय भूमि लगभग 9097.142 हेक्टे,निजी भूमि का रकबा लगभग 35930.862 हे, इसमें भी सिंचित भूमि लगभग 35905 हेक्टेयर और असिंचित भूमि लगभग 25.012 हेक्टेयर भूमि है।खेती योग्य पड़ती भूमि 25.012 हेक्टेयर जबकि तहसील क्षेत्र में लगभग 2057.641 हेक्टेयर भूमि चरनोई भूमी और गौ बैठान की लगभग 365.443 हेक्टेयर भूमि आंकड़ों के हिसाब से है। लेकिन धरातल पर आंकड़े कुछ और ही बता रहें हैं।आज स्थिति यह है कि गांवों में चरनोई भूमी गौ बैठान की भूमि लगभग नदारत है।इस भूमि के साथ साथ शासकीय भूमि पर दबंगों ने जमीनों को कब्जे में लेकर अपनी फसलें लहलहा रहे हैं। ऊपर से सुरक्षा की दृष्टि से तार बाड़ी लगा रखी है।अब मवेशी जायें तो कहां जायें।वहीं स्तिथि यहां तक देखने को मिल रही है कि गांवों में तालाबों और शमशान के नाम पर लाखों रुपए मस्टर रोल और पंचायत के खातों से आहरित तो हो गये लेकिन धरातल पर आज स्थिति कुछ और देखने को मिल रही है।

***मिट्टी के वर्तन बनाने वाली आरक्षित जमीन नदारत**- ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के वर्तन बनाने वालों को कुम्हरगढा के नाम से भूमी आरक्षित रहती है लेकिन यह जमीन गांव से ही नदारत है। बेचारे कुम्हार समुदाय के लोग बाहर मिट्टी ढोकर लाने और फिर बर्तनों को या खेल खिलौनों को पकाने के भट्टा लगाने के लिए आरजू मिन्नत करते हुए देखे सुने जाते हैं।

***गौ शालाओं की गंभीर स्थिति**- सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह देखने में आया है कि शासन द्वारा निराश्रित मवेशियों के उचित रखरखाव को लेकर भारी भरकम राशि गौ शालाओं के नाम पर मुहैया कराई गई है लेकिन वास्तव में आज चांवरपाठा विकास खंड में गौ शालाओं की गंभीर स्थिति बनी हुई है।जिस शासकीय भूमि पर गौ शालाओं का निर्माण और जमीन आरक्षित की गई है उसमें केवल और केवल प्रभावशालियों का ही कब्जा बरकरार है। गौ शालाओं के निर्माण के नाम पर राशि तो पंचायत के खातों से पूरी खर्च हो गई लेकिन ना तो अभी गौ शालायें पूरी तरह से बनीं हुई है। और ना ही इन निराश्रित मवेशियों की उचित व्यवस्था बनाई गई है। प्रतिदिन सड़कों पर बड़ी संख्या में मवेशियों के मृत शरीर या घायल अवस्था में सड़क किनारे कराहते हुए देखे जा रहे हैं।चंद गौ सेवक ही इनकी वेदना देख इनकी परवरिश में ही संलग्न बनें रहते हैं। अधिकारियों द्वारा जब कभी फुर्सत मिल जाती है तो यदि गौ शालाओं के निरीक्षण करने जाते हैं तो मवेशियों को चरने जाने की बात कहकर टाल दी जाती है या फिर अन्य व्यवस्थाओं के चलते वह भी संतुष्ट होकर चले जाते हैं।

***शासकीय भूमि पर सबकी चुप्पी**- सबसे बड़ी विसंगति पूर्ण स्तिथि यह बनीं हुई है कि तहसील क्षेत्र की शासकीय भूमि पर सभी जवाबदारों की चुप्पी बनीं हुई है। स्तिथि यह बनीं हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवन बनाने के लिए जमीन निकालने ऐड़ी चोटी की जोर अजमाइश करनी पड़ती है। तहसील क्षेत्र में कुछ ऐसे भी उदाहरण है कि आदिवासियों को बंटित जमीन पर आज तक काबिज नहीं हो सके हैं दबंगों के द्वारा ही जोता जा रहा है। ऐसे मामलों को यदि राजस्व कार्यालय में शिकायतें भी हुई है तो।या तो उनके आवेदनों की फाइलें ही गायब हो जाती है या फिर सुनाई ही नहीं।

***सबसे ज्यादा मामलें राजस्व विभाग में**- तेंदूखेड़ा तहसील क्षेत्र में आज कल बड़े ही अजीबो-गरीब गरीब कारनामें चल रहे हैं जिसकी सर्वत्र चर्चाएं भी व्याप्त हैं।आये दिन किसान संघ के अलावा अन्य किसान फोती नामांतरण बटाकन बंटवारे से लेकर 250 के मामलों में सालों से तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की छात्रों को जानकारी दे रहे गायत्री परिजन

तेंदूखेड़ा। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देशन में मानवीय गरिमा का बोध कराने सकारात्मक दृष्टिकोण परिष्कृत अभिरुचियां कर्तव्यनिष्ठा का जागरण करने विचारों में प्रखरता लाने तनाव अवसाद मुक्ति दिलाने दुर्व्यसनों से छुटकारा दिलाने राष्ट्र गौरव के सम्मान व्यक्तित्व के निर्माण तथा सुसंस्कारिता का जागरण करने के उद्देश्य से संपूर्ण भारत वर्ष में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन विगत 31 वर्षों से किया जा रहा है।वर्ष 1994 में गायत्री शक्तिपीठ भोपाल से शुरू हुई थी जो आज 22 राज्यों में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित हो रही है।यह परीक्षा एक ही दिन एक ही समय में गायत्री परिवार के सेवाभावी परिजनों द्वारा अध्यापकों के सहयोग से ओ एम आर शीट से संपन्न कराई जाती है।इस परीक्षा में अलग-अलग तीन केडर बनाये गये हैं जो कक्षा 5 एवं 6 कक्षा 7 से 12 वीं तथा महाविद्यालय स्तर शामिल हैं।इस परीक्षा में समाज निर्माण जीवन जीने की कला जीवन प्रबन्धन पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछें जानेवाले प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तथा छात्रों को पूर्व में एक पठनीय पुस्तिका भी प्रदान की जाती है। जिसमें रोचक जानकारी के साथ बच्चों का बौद्धिक विकास बढ़ता है। और परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने के तौर-तरीके भी साधारण मिला करते हैं। तहसील और जिला स्तर पर स्थान पाने वाले छात्रों को समारोह पूर्वक सम्मानित भी किया जाता है। तेंदूखेड़ा तहसील क्षेत्र के सभी गायत्री परिजन क्षेत्र के समस्त शालाओं में पहुंच कर छात्रों को पठनीय सामग्री प्रदान करते हुए भाग लेने प्रेरित कर रहे हैं।